राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–pr.rajbhavan@gmail.com
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के निचले स्तर तक अनुश्रवण हेतु सघन प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक है–राज्यपाल

पटना, 29 नवम्बर 2018

'राज्यपालों के सम्मेलन' में लिए गये निर्णयों के आलोक में राजभवन में आज राज्य के ग्यारह विभागों के अन्तर्गत महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्ग के लोगों आदि के लिए संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित प्रगति–प्रतिवेदन पर आवश्यक विचार–विमर्श के लिए महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आदि के वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। यह बैठक राष्ट्रपति सचिवालय एवं गृह मंत्रालय के निदेशानुरूप आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए आहूत थी।

बैठक को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने कहा कि आज एक नये भारत का निर्माण हो रहा है –एक ऐसे भारत का निर्माण, जहाँ हर गरीब आदमी को किसी–न–किसी सरकारी विकास एवं बड़ी कल्याणकारी योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि आज हर गरीब घर को रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि 'सौभाग्य योजना', 'उज्ज्वला योजना', जैसी कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं से निर्धन वर्ग–सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। आज सबको 'खाद्य–सुरक्षा योजना' का लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य–रक्षा के लिए विश्व की सबसे बड़ी 'आयुष्मान भारत योजना' प्रारंभ की गई है, जिसके जरिये यह सुनिश्चित होगा कि हर गरीब आदमी को पर्याप्त चिकित्सा–सुविधा मिल सके।

राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि आज योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों की कोई कमी नहीं है, धन–राशि का भी कोई अभाव नहीं है तथा इच्छाशक्ति भी भरपूर है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि निचले स्तर तक फुलप्रुफ प्रभावकारी अनुश्रवण व्यवस्था (Monitoring System) बहाल कर दी जाये।

राज्यपाल ने कहा कि अधिकारियों को भी पूरा यश मिले, इसके लिए जरूरी है कि लाभान्वित को हर हालत में संतुष्ट करते हुए योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में आवश्यकतानुसार नवाचारी प्रयोग भी होने चाहिए। श्री टंडन ने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में पर्याप्त सहयोग एवं समन्वय विकसित करने के उद्देश्य से इस वर्ष से राजभवन में भी 'संविधान दिवस' मनाये जाने की शुरूआत हुई है, जिसकी सबने सराहना की है।

आगे पृष्ठ...2 पर

राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार की शिकायतों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जायेगा एवं दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी।

राज्यपाल ने कहा कि हर प्रशासनिक तंत्र को आम जनता के प्रति ही अंततः जबावदेह होना है। संवैधानिक प्रधान के रूप में भारत सरकार के निदेशानुरूप योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार मेरा भी हरसंभव सहयोग यथासमय सबको उपलब्ध रहेगा।

बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आर॰के॰महाजन ने बताया कि –शेष बचे लगभग 1600 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी कर ली जायेगी। उन्होंने बताया कि 'नैक प्रत्ययन' के लिए महाविद्यालयों की तैयारी हेतु राज्य सरकार अपेक्षित पूरा आर्थिक सहयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु भी विश्वविद्यालयों को धन–राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि 'आयुष्मान भारत योजना' के सफल कार्यान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग में विशेष कोषांग गठित है। राज्यपाल ने 'जन औषधि केन्द्रों' की सूची उपलब्ध कराने को कहा; ताकि वे भी कुछ केन्द्रों की व्यवस्था को देख सकें। राज्यपाल द्वारा छोटे शहरों में भी बड़े प्राइवेट अस्पतालों की स्थापना की संभावना तलाशने का भी सुझाव दिया गया।

बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री एस॰ सिद्धार्थ को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में आबंटन–व्यय की स्थिति से संबंधित सूचनाएँ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि उसे गृह मंत्रालय एवं राष्ट्रपति सचिवालय की अपेक्षानुसार उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।

बैठक में सूचना एवं प्रावैधिकी सचिव श्री राहुल सिंह ने कहा कि राजभवन में आई॰टी॰ सेल के गठन तथा डैश बोर्ड संस्थापित करने हेतु 'रोड–मैप' तैयार करने के लिए यथाशीघ्र परामर्शी की सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी।

बैठक में यह भी बताया गया कि सभी विश्वविद्यालयों में अगले सत्र से 'University Management Information System' कार्यान्वित हो जाएगा। साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा भी जानकारी दी गई कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के सभी जिलों को खुले में शौचमुक्त (ओ॰डी॰एफ॰) घोषित करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहे हैं।

श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालयों से समन्वय बनाकर भी 'रोजगार मेलों' के आयोजन पर विचार चल रहा है एवं इस दिशा में भी शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने श्रम विभाग को रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन में विश्वविद्यालयों को सहयोग करने के लिए कहा।

आगे पृष्ठ...3 पर

बैठक में राष्ट्रपिता गाँधीजी के 150वें जयन्ती वर्ष में कला–संस्कृति विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की गई। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने राज्यपाल को बताया कि राज्य के सभी विद्यालयों में 'प्रार्थना' के बाद 'गाँधी–कथा–वाचन' नियमित रूप से हो रहा है तथा शिक्षा विभाग ने गाँधी–संदेश से संबंधित पुस्तकें ग्रामीण परिवारों के बीच वितरित किया है। राज्यपाल ने शिक्षा विभाग की इस पहल पर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की एवं अन्य राज्यों के लिए भी इसे अनुकरणीय बताया। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने वैसे स्पोर्ट्स फेडरेशनों' की बैठक महामहिम के साथ कराये जाने का अनुरोध किया, जो 'ओलम्पिक' एवं 'एशियाड' से जुड़े खेलों के हैं।

प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीणा ने बैठक में बताया कि पश्चिमी चंपारण बाँका एवं जमुई जिलों में अनुसूचित जनजाति के लभार्थियों के लिए विशेष योजनाएँ सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वतंत्रता–सेनानियों और शहीदों की पहचान कर संग्रहालय में उनसे संबंधित सामग्रियों को संग्रहित करने की विशेष योजना पर भी काम हो रहा है। श्री मीणा ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर उन्हीं वर्गों से आने वाले 'विकास मित्रों' के माध्यम से अनु॰जाति/अनु॰जनजाति के कल्याण की योजनाएँ सफलतापूर्वक संचालित कराई जा रही हैं।

बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने बैठक में उपस्थित संबंधित सभी विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों/अपर सचिवों/वरीय अधिकारियों से अनुरोध किया कि गृह विभाग एवं राष्ट्रपति सचिवालय के निदेशानुरूप अपेक्षित प्रतिवेदन राजभवन को कृपया एक सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाये, ताकि समेकित प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर उन्हें भेजा जा सके।

बैठक में विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के अतिरिक्त राज्यपाल सचिवालय के भी वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

.....